SHRI MOOL DHAND DAGA : West Bengal is accountable for this.

SHRI SATYAGOPAL MISRA : Why is he talking about West Bengal ?

MR. DEPUTY SPEAKER : He has got his own reasons.

(*Interruptions*)

SHRI MOOL CHAND DAGA : You have got so much amount ; you have not utilized that amount. The best way for you is to cry about it near the factory. You can have it there and you can resort to murder or other things. We know what has happened in West Bengal.

आप लोगों को तो और नीची गरदन करनी चाहिए कश्मीर वालों को। ये क्यों बोल रहे हैं। 6 अक्तूबर को क्या हुआ। आपकी गरदन तो और नीची होनी चाहिए। 6 अक्तूबर को क्या हुआ : जब वेस्टइंडीज से मैच हो रहा था......। (व्यवधान)

SHRI RAM LAL RAHI : I am on a point of order. (*Interruptions*)

PROF. SAIFUDDIN SOZ : What about Delhi ? Every day there is a murder. You are going to West Bengal ? You see the plunder and loot ; this is the Capital of India.

MR. DEPUTY SPEAKER : He is going to conclude. Now, it is 5.30

MR. Daga may continue next time. All of you come prepared. We go to the next subject—Half-an-hour discussion.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Grant of Loans to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Persons in Various States

MR. DEPUTY SPEAKER : We shall now take up discussion—Half-an-hour discussion regarding granting of loans to Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons.

SHRI RAM LAL RAHI (Misrikh) : Just two minutes, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER : No.

SHRI RAM LAL RAHI : ......*

MR. DEPUTY SPEAKER : Please do not record anything.

Are you raising a point of order or what ? No I do not allow.

SHRI RAM LAL RAHI : ......*

MR. DEPUTY SPEAKER : No, not allowed. What do you want to speak ? Please reserve i for Monday. Please do not record anything. Shri Ram Vilas Paswan. It have taken up Half-an-hour discussion. Unless hon. Members obey the Chair, we cannot conduct the House. I have gone to the next subject. You have not given any notie. I will give you one hour on Monday. Mr. Ram Vilas Paswan.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : It is your commitment. You must give one hour.

MR. DEPUTY SPEAKER : Yes. Now, Mr. Ram Vilas Paswan ; Half-an-hour discussion on granting of loans to Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons in various States.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आधे घण्टे की चर्चा हमारे प्रश्न संख्या-852 दिनांक 18 नवम्बर के अतारांकित प्रश्न से उठती है। आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति, जन-जाति या कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो सरकार द्वारा राशि दी जाती है, कितना उनके विकास पर खर्च किया जाता है, इसके बारे में मैंने लाइब्रेरी से सूचना मंगायी है जो छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में है। इसमें अध्याय-26 है जिसमें लिखा है "संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्त्वों में से एक तत्त्व में बताया गया है" कि राज्य जनता में दुर्बलता विभागों में विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की

*Not recorded

शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। इन निदेशक तत्वों को पंचवर्षीय योजनाओं में मूल रूप दिया गया है। इन योजनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों सहित सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान करने का प्रयत्न किया गया है। यह सब होते हुए भी विकास के तीन दशक पूरे हो गए हैं। अभी भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से सुविधा वंचित इन लोगों पर इन योजनाओं का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है।

छठी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है, उसमें लिखा है—बंधुआ मजदूरों में से भी अधिकांश अनुसूचित जातियों के हैं। इन दोनों जातियों की सामाजिक, आर्थिक दीनता के कारण ही उनमें पिछड़ापन समाया हुआ है। संवैधानिक निदेशों और सरकार द्वारा अपनाए गए वैधानिक और कार्यपालिका उपायों के बावजूद इनमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण आर्थिक समर्थन का अभाव है। यदि और इसके आगे जायेंगे तो इसमें लिखा है कि देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग दस करोड़ है। इनके पास बहुत कम परिसंपत्तियां हैं और ये सामान्य रूप से खेतीहर मजदूर, चमड़े का काम और अन्य कम आय के धंधों पर निर्भर रहते हैं। अनुसूचित जातियों की काम करने वाली जनसंख्या का 52 प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं और इसके विपरीत कृषि मजदूरों का 33 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है। अधिकतर बंधुआ मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं। इनकी साक्षरता का स्तर केवल 14.7 परसेन्ट है जबकि अखिल भारतीय स्तर 33.80 परसेन्ट है।

उसी तरह अनुसूचित जाति और जनजातियों के सम्बन्ध में है। सबसे विचारणीय बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पहली योजना थी उसमें क्रमिक योजनायें पिछड़े वर्ग के विशेष कार्यक्रमों के लिये थीं उनके लिये जो रुपया रखा गया और जो खर्च हुआ उसका यदि अनुपात देखेंगे तो पायेंगे कि पहली योजना में 39 करोड़ रुपया था और खर्च हुआ 30 करोड़, दूसरी योजना में 90 करोड़ और खर्च हुआ 79 करोड़, तीसरी योजना में 114 करोड़ और खर्चा हुआ 99 करोड़, चौथी योजना में 171 करोड़ और खर्चा 141 करोड़ और पांचवीं योजना227 करोड़ का प्रावधान था और खर्चा हुआ 1226 करोड़ तो मैं कह रहा था कि यह इनका लक्ष्य है।

अभी मैं एक सवाल देख रहा था जो इसी सदन में पूछा गया था 18 नवम्बर को कि क्या वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि उनके मंत्रालय तथा उनके विभाग द्वारा चलायी गयीं विभिन्न योजनाएं क्या हैं उनका ब्यौरा क्या है, उनका मार्ग निर्देश क्या है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को रियायतें, ऋण, सहायता, अनुदान एवं अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? जबाव में कहा गया यदि देखेंगे तो उसके मुताबिक 1980-81 में जो बेनीफिशियरीज हैं जिनका टोटल नम्बर 27,26,747 है, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स लोग हैं, जिनकी जनसंख्या 25 परसेन्ट है, तो उस कमजोर वर्ग का टोटल है 7,81,047। 1981-82 में 27,13,418 हैं। और इनमें से एस० सी० एस० टी० हैं 10,597। 1982-83 में 34,55,447 और इसमें से एस० सी० एस० टी० का टोटल नम्बर है 14,05,060। यह प्रश्न सं० 912 है। इसी प्रश्न के एक पैराग्राफ में इनसे यह पूछा गया था कि बोरोवर अकाउन्ट्स और अमाउन्ट आउटस्टेन्डिग क्या है? आप देखेंगे कि सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा दिये गये राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं: टोटल नम्बर आफ बोरोवर अकाउन्ट्स 29,25,278 और अमाउन्ट आउटस्टैन्डिग 25,779 और इसमें एस० सी० एस० टी० का जो परसेंटेज दिया हुआ है वह है 47.88 परसेंट।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मेरे पास प्रश्न

काफी हैं लेकिन जो जवाब आये हैं मुझे नहीं पता चल रहा है कि एक प्रश्न का ज़वाब दूसरे से टैली करता है कि नहीं ?

एक जगह इनसे पूछा गया था कि छठी पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्गों पर खर्च के लिये आपके यहां टोटल लक्ष्य कितना रखा गया था तो इनका जवाब मिला है कि 3 हज़ार करोड़ रुपया। एक तारांकित प्रश्न संख्या 897 में इनसे पूछा गया कि इसमें से खर्च कितना किया गया तो जवाब मिला कि उनके पास अभी तक पूरे आंकड़े नहीं हैं। लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध थे, उसके मुताबिक इन्होंने 3 साल के अन्दर 1470 करोड़ रुपया खर्च किया है जबकि 5 साल की योजना का लक्ष्य 3 हजार करोड़ रुपये का था।

मैं इसीलिये कह रहा हूं कि इस सरकार की जो नियत है चाहे कोई भी सरकार हो, इस पक्ष की हो या उस पक्ष की हो, उनकी नियत शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिडूयल्ड ट्राइब्ज और वीकर सैक्शन के प्रति साफ नहीं है। अगर कहीं-कहीं साफ भी रहती है, तो मशीनरी जो होती है, जैसे हथियार बहुत अच्छा हो लेकिन उस हथियार को चलाने के लिये कोई हाथ नहीं हो तो वह मशीनरी कारगर नहीं होती है, उसी तरह से इस वर्ग के लिये इनकी योजनाएं कारगर नहीं होती हैं।

मेरे पास प्रेस क्लिपिंग्ज हैं जिसमें छोटी सी बात है। इन्होंने हमारे जवाब में कहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों को 5 हजार रुपये तक हम बिना गारन्टी के देते हैं और अगर कोई उद्योग-धन्धा चलाना चाहे तो उसको बिना तीसरे पक्ष की गारन्टी के 25 हजार रुपये तक दे सकते हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय अपने जवाब में बतायें कि अब तक कितने ऐसे परिवार हैं जिनको 5 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की गई है और कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने 25 हज़ार रुपये की राशि उनके रोजगार के लिये बिना किसी गारन्टी लिये दी है ?

यह इनका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। आप अखबारों की कटिंग देखिये। "**नवभारत टाइम्स**" का 10 मई 1983 का अंक देखिये, इसका एक हैडिंग है "हरिजन और सरकारी भैंसे"। इन सरकारी भैंसों के बारे में इनके जर्नलिस्ट श्री महरउद्दीन खां ने गांव में जाकर सर्वेक्षण करके यह लिखा है। इससे पता चलता है, आप इसे सुनकर दंग रह जायेंगे, कि एक भैंस जिसकी कीमत 6 हजार रुपये बतलाई गई है, उसमें 3 हजार रुपये सरकार देती है और 3 हजार रुपये उसको देना पड़ता है, लेकिन भैंस की एक्चुअल कीमत 3 हजार रुपये इसमें बतलाई गई है। किसी की कीमत 2 हजार होती है लेकिन उसको 6 हजार रुपये में दिखलाया जाता है।

इस आर्टिकल में आंकड़ा दिखलाया गया है कि 16 भैंसे थीं लेकिन इन 16 में से 4 इतनी बूढ़ी और बीमार थीं कि वह मर गईं। बेचारे गरीब हरिजन ने कहा कि हम किसी तरह ऋण से उऋण हों तो वह बेचारा दूसरी भैंस को बेचने के लिये गया, उसने सोचा कि 6 हजार नहीं तो 4 5 हजार रुपये मिल जायेंगे लेकिन जब वह बेचने लगा तो उसको कहा गया कि इसकी कीमत डेढ़ हजार से ज्यादा नहीं है।

एक तरफ सरकार जो पसा देती है, उसमें कंजूसी करती है और जो पैसा देती है, उसका उपयोग नहीं होता है बल्कि दुरुपयोग होता है। इस देश के अनपढ़ लोग, गांव में रहने वाले लोग, इस देश और समाज के सबसे नीचे की पीढ़ी और इकाई के लोग जो देश की बुनियाद हैं, लगता यह है कि उनको ठगने के सिवाय, चौतरफ मार के सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा है।

हमारे बिहार का एक पेपर है "आर्यावर्त" इसका सर्कुलेशन बहुत है। इसके 10-5-83 के अंक में निकला है कि —

हरिजनों तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की दुहाई देने वाली राज्य की मौजूदा सरकार ने इन वर्गों के कल्याणकारी कार्यों की न केवल भारी उपेक्षा की है वरन तीन वर्षों में छह करोड़ रुपयों से अधिक सरेन्डर कर इन दलित तथा उपेक्षित वर्गों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को हमेशा के लिए क्षीण कर दिया है। "सरेन्डर" की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। 1980-81 में सिर्फ 45 लाख रुपये सरेन्डर हुये थे, जब कि 1981-82 में एक करोड़ तथा 1982-83 में लगभग 4 करोड़ 85 लाख रुपये सरेन्डर किये गये।

यह हमारे यहां का बिहार का मामला है।

फिर आप हिन्दुस्तान देखें, उसमें उसने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा है कि —

भारत सरकार के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा पिछले 32 वर्षों में उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 1011 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई जिसका उपयोग नहीं किया गया।

वर्ष 1974-75 से 1981-82 तक केन्द्र ने पिछड़ी जातियों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 68 करोड़ रुपये की धनराशि दी परन्तु मार्च 1982 तक इस राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया।

इसी तरीके से यह भरा हुआ है। आप शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट को देखें,कमीशन्स की रिपोर्ट को देखें, इन सारी रिपोर्टों को देखने के बाद सरकार द्वारा जो रेडियो और अखबारों के द्वारा सुबह से शाम तक अनुसूचित जाति और जनजाति की जय जयकार होती है उसको देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं सरकार से सीधा कहना चाहूंगा इस डिस्कशन के माध्यम से कि सरकार का सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व हो जाता है कि जो हिन्दुस्तान की आबादी का 25 परसेंट है उसके लिये सरकार ने अपने बजट में कितने परसेंट की अभी तक व्यवस्था की है ?

टोटल बजट का कितना परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए निर्धारित किया है ?

दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर छठी पंच वर्षीय योजना तक कितनी राशि इनके विकास और उत्थान के लिये रखी गई और उन पर कितना खर्चा हुआ ? जो अभी छठी पंच वर्षीय योजना है और अब तो हम लोग सातवीं योजना पर चलने वाले हैं, लेकिन इस छठी योजना के अन्तर्गत कितनी राशि का आवंटन किया गया था और उसमें से कितना खर्च किया गया ? कितने परिवारों को लाभान्वित करने का आप का लक्ष्य था और कितने परिवारों को आपने लाभान्वित किया है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बिना जमानत 5 हजार रुपये कितने परिवारों को दिये गये और रोजगार चलाने के लिए 25 हजार रुपये की राशि कितने परिवारों को दी गई ?

सरकार इस सदन में यह घोषणा भी करे कि जो अनुसूचित जाति और जन-जाति का टोटल परसेंटेज है उस परसेंटेज के मुताबिक उस के विकास और उत्थान के लिये सरकार खर्च करेगी। क्योंकि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास और उत्थान का मामला, उन की भलाई का मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है, फण्डामेंटल राइट्स के तहत उसको यह अधिकार दिया गया है तो क्या केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई मानिटरिंग सेल है जिसके माध्यम से वह देख रही है कि जो रुपया उनके लिये रखा गया है उसका सही उपयोग हो पाया है या नहीं और सही उपयोग नहीं हो पाया तो उसके लिए सरकार के पास कोई दण्ड का विधान है या नहीं ?

THE MINISTER OF STATE MINISTRY FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO): Sir, actually the banks have been correctly instructed by the Reserve Bank and the Government also that the weaker sections should be properly encouraged with loans in time and, according to our report, they have been following them. You will understand from the figures which I will give that the uumber of borrowers belonging to the Scheduled Castes and Tribes in the priority sector have increased from 12.07 lakhs in 1979 to 24.03 lakhs in June 1981.

Over the same period, the amount outstanding in these accounts had increased from Rs. 176.9 crores, i.e., 3.1 per cent of the total priority sector advances of scheduled commercial banks, to Rs. 416.7 crores, i.e., 4.4 per cent of the total priority sector advances of these banks. In other words, during the period from July 1979 to June 1981, of the increase of 40.1 lakh borrowal accounts in the total priority sector advances of scheduled commercial banks, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes accounts numbered about 12 lakhs, i.e., 29.8 per cent. In terms of the amount, the total increase in the outstanding priority sector advances of scheduled commercial banks between June 1979 and June 1981 was Rs. 3655 crores of which the Scheduled Castes and Scheduled Tribes borrowers accounts accounted for Rs. 239.8 crores, that is, 6.6 per cent of the total. Data regarding advances of scheduled commercial banks to priority sectors at the end of June 1979, 1980 and 1981 are here in the Annexure. I can give them if you want.

While giving instructions they have been told as follows :

A broader concept which encompasses all priority sectors has been evolved to comprise :

(a) Small and marginal farmers;

(b) Landless labourers;

(c) Tenant farmers/share croppers;

(d) Artisans, village and cottage industries;

(e) IRDP beneficiaries;

(f) Scheduled Castes/Scheduled Tribes; and

(g) DRI scheme beneficiaries.

These are the categories under which these nationalised banks are distributing the loans.

This category now covers almost all the poor beneficiaries of the new 20-Point Programme. In order to ensure that this section of borrowers receives increasing attention from the banks, it has been stipulate that it will account for not less than 25 per cent of the total priority sector credit of public sector banks by March 1985. In other words, since the priority sectors are to account for 40 per cent of the aggregate credit by that date, weaker section will account for 10 per cent of the aggregate credit of public sector banks. This is expected to give fillip to flow of credit to all weaker section borrowers, including Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons.

The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes borrowal accounts assisted by the public sector banks and the quantum of outstanding advances are being monitored by the Government regularly on a six-monthly basis. As part of this monitoring ehief executives of public sector bank which do not show adequate progress in financing Scheduled Castes and Scheduled Tribes borrowers are specifically addressed for initiating steps to provide larger quantum of credit assistance to Scheduled Castes and Scheduled Tribes borrowers. For public sector banks, bankwise data on advances to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are available and are here in the Annexure. If you want I can give you that also.

Then in respect of IRDP term credit which is mobilised, time the figure for 1980-81 is Rs. 289 crores, for 1981-82 it is Rs. 469 crores, for 1982-83 the figure is Rs. 714 crores. You can understand that from Rs. 289 crores in 1980-81, it has gone up this year to Rs. 714 crores.

SHRI RAM VILAS PASWAN : What is this figure of Rs. 714 crores ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is under IRDP programmes.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : How much

goes to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

SHRI PATTABHI RAMA RAO : I am telling you.

The target (expectation) was Rs. 3,000 crores in five years from 1980-81 to 1984-85.

The target of credit mobilisation is expected to be reached......

SHRI RAM VILAS PASWAN : Out of Rs. 3,000 crores how much money has been spent.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : By the end of Plan period 1985 it will be Rs. 3000 crores.

श्री राम लाल राही : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बतलाया है

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Rahi, the Minister is answering his question.

श्री रामलाल राही : मैं आप की आज्ञा मान लेता हूं लेकिन स्पष्टीकरण देना जरूरी था क्योंकि उनके बयान से गलतफहमी पैदा हो रही है ।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Mr. Minister has said Rs. 3,000 crores...

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is the target.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Minister, the target by 1985 is Rs. 3,000 crores. We are in 1983. By now how much has been spent ?

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Rs. 714 crores have been spent up till now.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Minister is wrong. I refer to Unstarred Question No. 897 dated the 18th November.

In 1980-81	...	Rs. 289 crores
In 1981-82	...	Rs. 467 crores
In 1982-83	...	Rs. 713 crores

The total comes to about Rs. 1470 crores.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : From IRDP till 1982-83 it is Rs. 1870 crores.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Thank you, Mr. Paswan. You have helped .

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Rahi, I think I will have to name you. I am sorry you are spoiling the discussion. I will name you and then you will feel sorry.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Rs. 1470 crores is the credit mobilised during the first three years—upto November, 1983. The level of amount deployed reached in 1982-83 is Rs. 714 crores. That is the figure which I have given earlier. At this level another Rs. 1500 crores may be mobilised in 1983-84 and 1984-85.

Banks have been advised to give primacy to the viability of the proposed productive ventures while considering applications from smaller borrowers, including SC/ST borrowers. Collateral security or third party guarantee is not to be asked for small loans upto Rs. 5,000 for purchase of moveable assets in the field of Agriculture and allied activities and upto Rs. 25,000 as composite loans in the sector of artisans and village and cottage industries and tiny units. There are no similar guidelines in regard to loans in transport, retail trade/business, etc. in bigger business.

Hon'ble Members may also know that the guarantees guidelines have been strictly observed all along and the Finance Minister has also recently written to the Chief Ministers of all the States about constituting local level committees to ensure proper response from banks to the credit base programe directed towards SC/ST and other weaker sections.

Banks have also been advised...

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : Hear, hear.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Paswan, Prof. Ranga says hear, hear.

18.00 Hrs.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Mr. Paswan is a very intelligent man. I know he understands things.

SHRI RAM VILAS PASWAN : He is telling "hear". I do not know what to hear.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Prof. Rangaji said like that. I am speaking in English. You know Hindi. That is the difficulty.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No. He also knows English. He is an advocate.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Now, Sir, banks have also been advised that efforts made to increase credit assistance to Scheduled Caste and Scheduled Tribe borrowers should specifically figure in the evaluation of the work of the regional managers, branch managers and field officers. At the zonal and head office level also, banks have been asked to place specific responsibility on specific officers to oversee the efforts being made by the branches to assist Scheduled Caste/Scheduled Tribe entrepreneures.

While specific ventures to be undertaken by Scheduled Caste/Scheduled Tribe borrowers will fall within the priority sectors, one specific programme in which Scheduled Caste/Scheduled Tribe persons have a certain allocation of the programme is the IRD Programme. This programme which envisages credit and subsidy support to 600 below the povertyline families per block every year, stipulates that at least 30% of the identified beneficiary families should be those belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes. The total number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe families assisted by banks and co-operatives increased from 7.8 lakh in 1980-81 to 10 lakhs in 1981-82 and to 14.06 lakhs in 1982-83.

The DRI scheme, drawn up to assist the weakest among the weaker sections, provides for loans for productive purposes at a nominal 4% rate of interest. The maximum amount of loan is, however, restricted to Rs. 6500. The banks have been advised to ensure their lendings under the scheme to one per cent of their aggregate advances at the end of the previous year. 40 per cent of advances under the Scheme are earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Only such persons whose family income from all sources does not exceed Rs. 3000 per annum in urban and semi-urban areas and Rs. 2000 per annum in rural areas and who do not own any land or the size of whose holdings do not exceed 1 acre in the case of irrigated land and 2.5 acres in the case of unirrigated land are eligible to borrow under this Scheme. In case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe borrowers, the land holding criteria have been waived provided they are otherwise eligible.

According to quick estimates made available by the Reserve Bank of India, the public sector banks and outstanding advances of Rs. 305. crores involving 32.2 lakh borrowal accounts under the DRI Scheme as at the end of December, 1982. Of this, Scheduled Caste/Scheduled Tribe borrowers accounted for Rs. 147 crores or 48% of the total DRI loaning, involving 15.6 lakh borrowal accounts.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : He has received all the answers from the questions. Now, he is convinced.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : He will never be convinced. You should know this. I am giving him all the facts.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has got all those figures. He is only verifying what you are saying is correct.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : He is quite intelligent. He understands the things. But still he wants from the Government.

SHRI RAM VILAS PASWAN : I want to know two or three points only and the Minister can reply within two or three minutes.

मैंने जो प्रश्न किया था कि अभी तक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेअर के लिये, विकास के लिए कितना पैसा रखा गया और उसमें से कितना खर्च हुआ। दूसरा प्रश्न मैंने यह किया था कि सिक्सथ फाईव इयर प्लान में कितने लोगों का जीवन स्तर उठाने का लक्ष्य रखा गया था और कितने लोग अभी तक लाभान्वित हुये हैं और कितने लोगों को आगे लाभान्वित करने की योजना है। ये प्रश्न मैंने पूछे थे।

SHRI PATTABHI RAMA RAO : I have given all the information that is available with me. But if the hon. Member wants any further information, let him put a question or write a letter to me, I will send him.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कमजोर वर्ग का मामला है और सरकार कमजोर वर्ग की भलाई करना चाहती है। यह कमजोर मामला है और इसको ताकत पहुंचाने के लिए हम इस सदन में चर्चा करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि सारी बात को बड़ी संजीदगी के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ सुना जाए।

मेरा कहना यह है कि ये जो सारी योजनाएं बनाई गई हैं वे इसलिये बनाई हैं कि संविधान में यह कहा गया है कि हम प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक सामानता देंगे और विषमताओं को पाटने के लिए ये सब प्रयास किये जा रहे हैं। यह किसी पर हम एहसान नहीं कर रहे हैं। इसलिये जो योजना बनाई जाती है उससे किसी का विरोध नहीं है। विरोध तो अब पैदा होता है जबकि इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की दृष्टि से कोई उपाय नहीं रह जाता।

अभी आपने एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के बारे में बताया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस विकास योजना में 80-81 से, 81-82 और 82-83 में कितना खर्च हुआ? आपका कहना यह है कि जितना कि तीन वर्षों में खर्च हुआ उससे अधिक आप आगे आने वाले दो वर्षों में खर्च करना चाहते हैं, या खर्च करने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष जो पैसा आपने इन लोगों को दिया, उस पैसे का लाभ उन लोगों को पहुंचा या नहीं पहुंचा? यह प्रश्न है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि उज्जैन जिले की एक बड़नगर तहसील को रजत जयन्ती ग्राम घोषित किया गया और उस गांव के 20 लोगों को ऋण दिया गया। उन 20 लोगों में से केवल दो लोग ही उस ऋण का उपयोग कर पाये, बाकी के लोग नहीं कर पाये। ऐसी स्थिति में जब आप रोजगार लोगों को दिलाना चाहते हैं और पांच हजार रुपये का ऋण देना चाहते हैं तो यह कैसे दिलायेंगे। होता क्या है कि पाँच हजार रुपये का ऋण वहां के बी० डी० ओ०, पशु चिकित्सा अधिकारी और बैंक के अफसर की राय से मिलता है। किन्तु यह ऋण दिलाने के लिए बी०डी०ओ० और चिकित्सा अधिकारी रिश्वत मांगते हैं। जो ऋण किसी को दिलाया जाता है उसमें से वे रिश्वत काट लेते हैं उसके बाद वह ऋण किसी को मिल पाता है। किश्तें उसको चुकानी पड़ती हैं। किश्तें चुकाने के लिये उसके पास पैसा नहीं होता और उसको आजीविका के लिये दिये गये भैंस, बकरी बेचने पड़ते हैं। इसलिये पैसे का सदुपयोग हो यह मेरा आग्रह है योजना से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन पैसा सही आदमी तक पहुंच नहीं पाता। मैंने इस बात को देखा है। कमजोर वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए 1500 रुपये का ऋण दिया गया। क्या 1500 रुपये में मकान बन सकता है। मकान बनने से पहले ही ढह गये। केवल बातों से काम नहीं होगा।

प्रश्न यहां पर इसलिये पूछे जाते हैं कि उनके जरिये सरकार को सही जानकारी मिले और सरकार अपने कार्यों में सुधार कर सके। इसलिए मेरा कहना यह है कि पिछले सालों में कितना पैसा दिया गया और क्या वह कमजोर वर्ग तक पहुंचा, इसकी जांच करने के लिए सरसर के पास क्या व्यवस्था है। आगे आने वाले वर्षों में आप 1500 करोड़ रुपया और देने वाले हैं। उसको ठीक जगह तक पहुंचाने की आपके पास क्या योजना है। बैंकों से कमजोर वर्गों को लोन नहीं मिलता। चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनको बेरोजगार रहना पड़ता है। इस तरह के गरीब वर्ग के, अनुसूचित जाति के 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 80 प्रतिशत गांवों में रहते हैं। उनके लिये आप चाहे जितनी योजनाएं

बनाए, उनको लाभ मिलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो श्रमिक वर्ग के हामी रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह से उनका शोषण नहीं होना चाहिये। उनको मदद ठीक से मिलनी चाहिये, लोग भूखों मर रहे हैं। इसलिये जो पैसा अलाट किया गया है वह ठीक लोगों तक पहुंचे, उसका ठीक उपयोग हो, इसको देखने के लिए आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं ?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : What is the total percentage of Scheduled Castes and Tribes population in each State ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : In each State ?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Whatever he can, he can give. He should assure that he will supply the information.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He can furnish that information, if it is not available, afterwards.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : He can supply.

And what percentage of them had got loans from the nationalised banks ?

Is there any Special Programme of Government in backward States and districts to give loans to Scheduled Castes and Tribes and, if so, what are those Special Programmes ?

Is it a fact that the Scheduled Castes and Tribes are being unnecessarily harassed by the bank authorities while giving loans and that the Scheduled Castes and Tribes are being compelled to give bribes ranging from 5 to 10% of the loans ? There is a widespread rumour to this effect. Is it a fact that corruption has entered into the banks and, if so, what measures are you going to take to correct it ?

An Hon. Member of this House Shri Bhogendra Jha has complained during the last session that in his district Madhubani in Bihar, notices were issued to repay the arrears of loans against 22 persons who never took loans from the banks. Has the Hon. Minister enquired into this anomaly ? If so, what action has the Hon. Minister taken against such officers who indulged in appalling anomalies ?

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : The hon. Minister has given various data and he has stated about the land distributed among the Harijans and all that. But the point is whether it was really distributed.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : How can I say that ? The local people must know.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I am asking the question from the Minister, from the Government.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : We have given the figures from the government side, what the banks have supplied.

SHRI HARIKESH BAHADUR : That is why I want to criticise the figures. My point is that these figures are absolutely incorrect....

SHRI PATTABHI RAMA RAO : No, Sir. I can accept only if he shows definite or specific cases.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can bring specific cases to the notice of the Minister as Mr. Ramavatar Shastri has cited some 22 or 23 cases.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Today it has become very difficult to prove anything because there is a lot of bungling in the distribution. It is always said that so much land has been distributed, so many buffaloes have been distributed, so much money has been distributed. But, in fact, if you really inquire into it, you will find that there is a lot of corruption, there is bungling, there are malpractices, fraud and everything else. So far as the IRD Plan is concerned, we are finding that most of the money is being taken away by the bank officials, State Government officials and some brokers at the local level. Whatever machinery is there with the State Government, that is not functioning properly. It is a very serious matter. My point is not

that I am charging the Minister that he is solely responsible for that. Ultimately who will look into it ? It is the Government has which to look into it, which has to evolve an effective implementation machinery so that money reaches the people for whom it is meant.

MR. DEPUTY-SPEAKER : People's representatives must check these things and bring to the notice of the executive.

SHRI HARIKESH BAHADUR : We are checking.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Is there any provision for that ? How can a representative go and ask ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : If they are generalised, then no action can be taken by the executive. You must cite some specific instances.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I agree with you to what you are saying. But the unfortunate part is that, whenever such type of things are brought to the notice of the persons concerned, the officials or the Ministers who have to look into them, most of the time we find that they do not want to take any action against the persons who are indulging in this kind of corruption. At the same time it becomes difficult for us to prove that this bungling has really taken place. It is a great difficulty. At the same time we are also not authorised to take any action against those people in spite of the fact that sometimes we see that such type of bunglings are taking place before our very eyes ; we are helpless, we cannot do anything ; we can simply report and whenever we report, we find that no action is taken. That is also very unfortunate. Therefore, in view of these facts which I have just described here, I would like to know from the hon. Minister whether he is going to evolve an effective machinery for the implementation of all these programmes and to see that the money which is being given by the Government really reaches the needy people. This is the main thing. The Central Government has got the responsibility to look after the Harijans and to work for the welfare of the Harijans according to the Constitution of this country. It will not be wise to leave it only to the State Governments. That is why I want to know whether Government has got any plan or proposal to set up any machinery to look into the implementation of these schemes. Most of the time we find that the money which is given to the State Governments is being surrendered, that it is not being properly distributed. I want to know what the hon. Minister is going to do to stop this practice also.

These are my specific questions.

SHRI MOOL CHAND DAGA : What is the plan ? There are 5,000 and odd Blocks in the whole country. In each block we identify 600 families each year. Now among those identified families which are below poverty line, what is the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes families which have been given loans in the last three years ? If you have got the figures, you can kindly tell us....

PROF. N.G. RANGA : Otherwise later.

SHRI MOOL CHAND DAGA : I have no objection. I simply want to know. Certain families have been identified by a committee. The Committee goes to the spot, identifies the families. Your object is to bring 1,00,15,000 people above the poverty line. That is your object so that all people can be brought above the poverty line.

A specific question I would like to put is : what is the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes families which are below the poverty line and in each block and in each State how many families have been given loan. He may not give the figures just now, he can give us later on.

Then I want to know whether the loan is given by a committee of officers— not of either BDO or the Pradhan or the bank officer. It does not come before the representative of the people. I want to know whether any representative of people is associated with the loan committee or not.

The third thing which I am asking is : after three years of continuous efforts, are you in a position to tell us to-day each year how many families belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have come above the poverty line and have crossed that limit and they are not now considered poor.